(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Use of voting machines

*271. SHRI K. R. MALKANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that although thousands of voting machines are available, these are not being used anywhere;

(b) whether Government would consider using the available machines, particularly in the regions where booth-capturing and rigging are widespread;

(c) whether it is also a fact that Government are not manufacturing enough voting machines to cater to the needs of the whole country only for reasons of cost;

(d) what would be the estimated cost of these machines if they were manufactured on a large scale; and

(e) whether Government consider that economy on voting machines is more important than the fairness of ©lections?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) and (b) Yes, Sir. The Government, however, advised the Election Commission of India in May 1993 to use the existing electronic voting machines in the general elections to the National Capital Territory of Delhi Assembly and other elections, wherever feasible. However, according to the Election Commission of India it could not use these machines in these elections due to a variety of reasons.

(c) to (e) A decision to procure additional electronic voting machines to cover the entire country would be taken only after the efficacy of the existing machines been tested in elections.

सौराष्ट्र में उच्च न्यायालय की पीठ

*272. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सौराष्ट्र में गुजरात उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना करने के संबंध में अब तक क्या कदम उठाये हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई प्रति अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को इस संदर्भ में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सौराष्ट्र क्षेत्र में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने में कौन-कौन सी अड़चनें पेश आ रही हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (छ) सौराष्ट्र में गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित किए जाने के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान चार अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। गुजरात सरकार से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण केन्द्रीय सरकार के लिए इस मामले में कोई कार्रवाई करना संभव नहीं हो पाया है।